www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 || अंक 334 || लखनऊ
बुधवार
11 मार्च 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 06:20
सूर्यास्त: 06:13
अधिकतम: 35°00
न्यूनतम: 20°00

» पेज 03

विशेष समाचार: जंग के कारण कच्चे तेल के दाम... » पेज 02 | लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य... » पेज 04 | मिडिल ईस्ट तनाव के बीच...

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब ओला, उबर को भी कराना होगा पंजीकरण

यूपी के 12,200 गांव तक चलेंगी सरकारी बसें

मुहर

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण आबादी को शहरों से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था में बड़े सुधार का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए, जिसमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी गई है। योगी सरकार ने ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026' को स्वीकृति दे दी गई। इस योजना के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचेगी। साथ ही, अब प्रदेश में ओला-ऊबर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 12,200 गांवों तक बसें नहीं पहुंच रही थीं। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बसें पहुंचेंगी। इन बसों को परमिट एवं टैक्स से मुक्त रखा गया है। इससे प्रदेश की बड़ी ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। ये बसें चलाने की अनुमति निजी लोगों को मिलेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसमें सीडीओ, एसपी, एआरटीओ, एआरएम सदस्य होंगे। ये बसें रात में गांव में ही रुकेंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि सुबह ब्लॉक एवं तहसील होते हुए ये बसें सुबह 10 बजे तक जनपद मुख्यालय तक पहुंचेंगी।

>> (शेष पेज 04 पर)

सुबह से शाम तक बसें डायवर्ट

परिवहन मंत्री ने बताया कि सुबह 10 से शाम चार बजे तक इन बसों को डायवर्ट करेंगे। इसके बाद ये बसें दूरी के हिसाब से अधिकतम शाम 8 बजे तक गांव में पहुंच जाएंगी। इन बसों के ड्राइवर, कंडक्टर व क्लीनर आसपास गांव के लोग ही होंगे, जिससे रात में गांव में रुकने और सुबह आने में उन्हें परेशानी नहीं होगी। इन बसों की औसत आयु 15 वर्ष रहेगी, लेकिन पहले 10 साल के लिए ही इन्हें परिचालन की इजाजत दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी स्थानीय स्तर पर किराया निर्धारण करेगी। इसका टिकट भी सस्ता रहेगा। इन्हें परमिट एवं टैक्स की आवश्यक्ता नहीं होगी। इससे बस चलाने वालों को लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य आमजन को बेहतर सुविधा मुहैया कराना है।

"मंत्री ने कहा कि आवेदन की फीस 25 हजार रुपये होगी। वहीं, 50 से 100 या इससे अधिक गाड़ी चलाने वाली कंपनी की लाइसेंसिंग फीस पांच लाख रुपये होगी। रिन्युअल हर पांच साल पर होता रहेगा। रिन्युअल के लिए 5000 रुपये देना होगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि ऐसा ऐप भी विकसित करेंगे होगा।"

अहम प्रस्तावों को जानिए...

- » उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैक्स को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना 2026 जारी की जाएगी।
- » उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन किया जाएगा।
- » प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी जाएगी।
- » मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए राशि जारी की जाएगी।
- » अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने के लिए वशिष्ठ कुंड, पगरना हवेली अवध की कुल 2500 वर्गमीटर भूमि अयोध्या नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
- » आवासों का बकाया टैक्स जमा कराने के लिए की एक मुश्त समाधान योजना 2026 लागू करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- » अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एक्सप्रेस-वे के पास मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना के लिए विकास कार्य को मंजूरी दी जा सकती है।

योजना किस तरह जमीन पर उतरेगी?

- मंत्री ने बताया- योजना के तहत गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट में भारी रियायत दी जाएगी या परमिट में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
- गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, आसपास के रूट के 15-20 गांवों, ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी।
- जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर उन्हीं गांवों से होते हुए वापस रात 8 बजे उसी गांव में पहुंचेगी, जहां से वह शुरु हुई थी।
- इस सुविधा से ग्रामीणों को अपनी फसल ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंचाने में आसानी होगी। किसानों, महिलाओं के साथ विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा।

यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस बीमा

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के एडेड डिग्री कॉलेज में कार्यरत नियमित और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। इन्हें कैशलेस इलाज के अलावा पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों और स्टेट यूनिवर्सिटी में नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, प्रदेश में करीब 1 लाख गांवों में से 12,200 गांवों में अभी भी बस सुविधा नहीं है। इन गांवों में बस सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत यूपी रोडवेज और प्राइवेट बसों का गांवों तक संचालन शुरु किया जाएगा।

ओला-ऊबर का भी रजिस्ट्रेशन

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि यूपी में अब ओला एवं उबर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है। भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा। ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था।

"ट्रम्प ने कहा है कि वह ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह बातचीत की शर्तों पर निर्भर करेगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रम्प से जब तेहरान के साथ वार्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है।"

ईरान पर आज की रात भारी

ट्रंप की खुली धमकी के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया बी-52 बॉम्बर का वीडियो

जंग

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 11वां दिन है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि मंगलवार को ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जाएंगे। हेगसेथ के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बमवर्षक विमान शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही हैं और वह बुरी तरह हार रहा है। वहीं ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा है कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि ईरानी लोग अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते। लारीजानी ने कहा कि पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लारीजानी ने ट्रम्प को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि ईरान को मारने के चक्कर में वे खुद ही खत्म हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप खेलने गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम को सरकार ने देश लौटने का भरोसा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खिलाड़ियों को "खुले दिल से" स्वागत के साथ वापस बुलाया जा रहा है।

>> (शेष पेज 04 पर)

ईरानी राष्ट्रपति बोले- हमें मिटाने का सपना देखने वाले इतिहास नहीं जानते

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि कोई भी ताकत ईरान को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ईरान कम से कम 6,000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान कायम रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में पजशकियान ने कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने का सपना देखते हैं, वे इतिहास को नहीं समझते। उनके मुताबिक कई आक्रांताओं ने ईरान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। उन्होंने कहा कि हमलावर आते-जाते रहे, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा है और आगे भी रहेगा।

डच अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण दूतावास की गतिविधियों को फिलहाल ईरान से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है।

नीदरलैंड ईरानी दूतावास से अपना स्टाफ हटाएगा

नीदरलैंड ने ईरान में बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच तेहरान स्थित अपने दूतावास से स्टाफ हटाने का फैसला किया है। डच सरकार ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए दूतावास की गतिविधियां अस्थायी रूप से अजरबैजान की राजधानी बाकू से संचालित की जाएंगी।

सरकार के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ते जोखिम को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हालात सामान्य होने के बाद व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जाएगी।

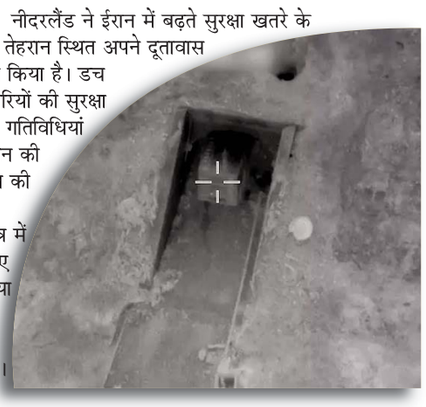

फास्ट न्यूज

पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा : ज्ञानेश कुमार

कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का मकसद है कि सभी सही वोटर को वोट देने का अधिकार मिले और कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो।

सीबीएसई के 12वीं के पेपर पर गाने का क्यूआर कोड

नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में मैथ के पेपर पर छपे सिक्योरिटी क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यू-ट्यूब की लिंक ओपन हो रही है। यह लिंक 39 साल पुराने इंग्लिश सॉन्ग 'रिकरोल' की है।

9 मार्च को हुए इस पेपर पर सीबीएसई ने कहा- क्यूआर स्कैन करने पर यू-ट्यूब लिंक ओपन हो रही है। लेकिन एग्जाम पेपर भी असली हैं। इस मामले में एग्जाम पेपर की सुरक्षा से समझौता नहीं हुआ है। एग्जाम पेपर की ऑथेंटिसिटी सुरक्षित है और आगे की परीक्षाओं में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल, कुछ छात्रों का कहना था कि उनके स्कैन करने पर सच में यूट्यूब पर गाने कि लिंक खुल रही थीं।

किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी

सोनीपत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह सोनीपत के मदीना गांव में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। ये वही किसान संजय मलिक हैं, जिनके खेत में राहुल ने तीन साल पहले ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई की थी। सुबह करीब सवा 10 बजे जैसे ही राहुल गांव में अपनी कार से उतरे उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। सिक्योरिटी टीम के साथ राहुल ने झुककर उसे उठाया। राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहना कर स्वागत किया गया।

जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया

सेना को दो आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी

तमसा संकेत, एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के झंगर-नौशेरा सेक्टर में LoC पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। भारतीय सेना ने बताया कि 10 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर झंगर-नौशेरा के इलाके में दो आतंकवादियों की हरकत का पता चला था। सेना ने बताया कि सैनिकों ने तेजी से काम किया, और घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। दूसरे आतंकवादी की तलाश जारी है। सेना के मुताबिक जमीन और हवाई निगरानी की मदद ली जा रही है। पिछले 5 दिनों में जम्मू-कश्मीर के राजौरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। इससे पहले 23 फरवरी को भारतीय सेना की व्हाइट

नाइट कोर ने X पर 7 आतंकियों की फोटो पोस्ट की और लिखा था कि 326 दिन के बाद किश्तवाड़ से आतंक के नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया है। पोस्ट में बताया गया था कि इन आतंकियों में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मारा गया है। सैफुल्लाह किश्तवाड़ में आतंक का सरगना था। व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि किश्तवाड़ में उनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF समेत सेना की इंटेलीजेंस एजेंसी भी शामिल रहीं।

स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

गोगोई बोले- राहुल को 20 बार टोका गया, रिजिजू का जवाब- प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ। मंगलवार को करीब 7 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका-टोका गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाईं।

66 संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं। किसी और की बात नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।

प्रियंका ने कहा- राहुल की सच्चाई इनसे पचती ही नहीं है

प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं। वह नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होके इनके सामने सच बोल देते हैं। सच्चाई वो जो बोलते हैं वह इनसे पचती नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध 2003 के इराक युद्ध जैसा नहीं होगा। उस समय अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और फिर वहां सालों तक फंसा रहा, सरकार बनाने और देश को संभालने की कोशिश करता रहा। इस बार ऐसा नहीं होगा।

अमेरिकी अधिकारी बोले- 3 टारगेट्स पर काम कर रही सेना

अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एयर फोर्स जनरल डैन केन ने कहा- अमेरिकी सेना फिलहाल तीन मिलिट्री टारगेट्स पर ध्यान दे रही है।

पहला- ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन क्षमता को नष्ट करना, ताकि वे अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देशों पर हमले न कर सकें।

दूसरा- ईरानी नौसेना पर लगातार हमले करना, ताकि वह होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए आवाजाही और गतिविधियां जारी न रख सके।

तीसरा- ईरान के सैन्य और औद्योगिक ढांचे के अंदर तक जाकर कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि आने वाले कई सालों तक ईरानी शासन अमेरिका और उसके साझेदारों पर हमला न कर सके और अपनी सीमाओं के बाहर ताकत न दिखा सके।

गोगोई बोले- बिरला बोलने नहीं देते, माइक बंद किया

- 2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। स्पीकर सर ने उनके तर्क पर सबूत देने का कहा।
- 9 फरवरी को शशि थरूर जब बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि बोलिए, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं जब माइक ऑफ किया गया हो। संसद में ऐसी नई-नई चीजें हो रही हैं।
- आज महिला सांसदों के उद्देश्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओम बिरला जी ने पीएम मोदी के समय कहा था कि महिला सांसदों ने पीएम की चेयर घेर ली है। उनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिरला ने किस आधार पर महिला सांसदों पर ये आरोप लगाए।

फैसला : संसद फैसला करे, शरियत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की आशंका

यूसीसी लागू करने का समय आ गया : सुप्रीम कोर्ट

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का समय आ गया है। इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। कोर्ट शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन धाराओं से मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप था। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा- शरियत कानून की धाराएं रद्द कर दी गईं तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता

है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मुस्लिम परिवार में संपत्ति या शादी से जुड़ा विवाद होता है, तो अदालत शरियत के आधार पर फैसला कर सकती है। हालांकि, यह कानून केवल निजी मामलों पर लागू होता है। चोरी, हत्या या अन्य आपराधिक मामलों में देश का सामान्य कानून ही लागू होता है। समय-समय पर इस कानून को लेकर बहस होती रही है, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि कुछ मामलों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता।

मुसलमानों के परिवारिक मामलों में लागू होता है शरियत कानून 1937

शरियत कानून 1937, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया एक कानून है। इसका उद्देश्य यह तय करना था कि भारत में मुसलमानों के निजी और पारिवारिक मामलों में इस्लामी कानून यानी शरियत लागू होगा। इससे पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अलग परंपराएं चलती थीं, जिससे फैसलों में एकरूपता नहीं थी। इस कानून के लागू होने के बाद शादी (निकाह), तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत यानी संपत्ति का बंटवारा, वक्फ और परिवार से जुड़े अन्य मामलों में शरियत के नियम मान्य माने गए।

भारत में केवल उत्तराखंड में यूसीसी लागू

भारत में अभी केवल उत्तराखंड में UCC लागू है। वहां 28 जनवरी 2025 को UCC लागू किया गया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। यूसीसी लागू होने से राजय में 5 नियम सख्ती से लागू हुए-

- शादी चाहे किसी भी धर्म के रीति-रिवाज से हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 60 दिन में रजिस्ट्रेशन न होने पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
- शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल जरूरी है।
- शादी और तलाक के नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू होंगे। यानी अलग-अलग धर्मों में अलग कानून नहीं रहेगा।

40 लाख महिलाओं के खाते में ₹9000 ट्रांसफर

सीएम बोले-चुनाव से इसका कोई लेनादेना नहीं

घोषणा

तमसा संकेत, एजेंसी

गुवाहाटी। असम में राज्य सरकार की ओरुनोडोई (अरुणोदय) स्कीम के तहत मंगलवार को 40 लाख महिलाओं के खाते में 9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस स्कीन को 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को हर महीने 1,250 रुपये मिलते हैं। असम सीएम ने इससे पहले घोषणा की थी कि इस साल जनवरी से चार महीने का पेमेंट, बोहाग बिहू के जश्न के लिए एक्स्ट्रा रकम के साथ मार्च में एक साथ दिया जाएगा।, जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में कहा कि यह कोई चुनावी फ्रीबी नहीं है, बल्कि

असम मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की।

महिला लाभार्थियों के प्रति सरकार के दयालु रवैये को दिखाता है। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सराम ने अपने पोस्ट में कहा कि 40 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 3,600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई चुनावी फ्रीबी नहीं है।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

तूल न दें एनसीईआरटी की भूल को

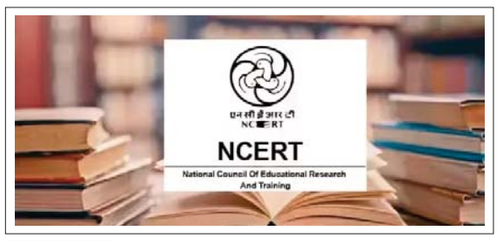

गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) की कक्षा आठ की एक पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक पाठ था। न्यायालय ने इसे लापरवाह और तिरस्कारपूर्ण माना। उसने और भी बहुत कुछ कहा, जैसे कि इसके पीछे गहरी साजिश है। यह सही प्रश्न पूछा जा रहा है कि केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर ही अलग पाठ क्यों? हालांकि बाद में पता चला कि इसके पहले राजनीति तथा नौकरशाही में कदाचरण पर चर्चा हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी को इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखना है। संभवतः अध्यापकों और एनसीईआरटी ने केवल न्याय-व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर अलग से पाठ लिखकर भूल की है और भूल करना अपराध नहीं है। भूलें अज्ञान या अनुभवहीनता के कारण हो सकती हैं और अधिकांश अवसरों पर सुधारी जा सकती हैं। इसके लिए उस संस्था को अपमानित करना आवश्यक नहीं। उस पुस्तक के पाठ में जो लिखा है, वह कितना सही या गलत है, यह तो लोग नहीं जानते, लेकिन न्यायपालिका के रुख पर देशव्यापी चर्चा हो रही है।

एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। तब से यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक थिंकटैंक बनकर उभरी और उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख बनाई है। देश की हर व्यवस्था को चलाने वाले अधिकांश लोग तथा विद्वत वर्ग एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़कर जीवन में आगे बढ़े हैं और संस्था के प्रति आदरभाव रखते हैं। देश की उच्चतम प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के लिए तैयारी करने वाले युवा एनसीईआरटी की पुस्तकों का पूर्ण विश्वास से अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी 'व्यक्ति से व्यक्तित्व' का निर्माण करती है और नैतिकता, आचारनीति तथा मूल्य-आधारित जीवन जीने के लिए देश के भविष्य को संवारने में संलग्न है। देश की शिक्षा की समय के साथ गतिशीलता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर एनसीईआरटी नए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पुस्तकें बनाती है।

इस प्रक्रिया में सारे देश से आमंत्रित विशेषज्ञ भाग लेते हैं और प्रत्येक पांडुलिपि अनेक स्तरों पर पूरी तरह परखी जाती है। एनसीईआरटी की आलोचना भी अनेक अवसरों पर होती है, जिसके पीछे प्रायः वैचारिक/राजनीतिक प्रतिबद्धताएं ही हावी होती हैं। एनसीईआरटी से गलतियां भी होती रही हैं, लेकिन सामने आते ही सुधारी जाती हैं। खेद व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि एक बार एक किताब में कुछ पैराग्राफ लेखक ने नकल कर लिखे थे। मामला सामने आने पर त्वरित सुधार किए गए। एक अन्य पुस्तक में मेडागास्कर को अरब सागर में दिखाया गया था। उसे भी पुनः सुधार कर हिंद महासागर किया गया। जाहिर है एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानी और पुस्तकों में परिवर्तन किए, लेकिन किसी ने किसी भी स्तर पर इसके पीछे किसी सोची-समझी साजिश की बात नहीं कही। यह संस्था सभी की है, देश की है। एनसीईआरटी की हर पुस्तक के प्रकाशन के लिए अंतिम स्वीकृति निदेशक की ही होती है। नैतिक जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वर्तमान प्रकरण में भी ऐसा ही माना जाना चाहिए। 2002-03 में इतिहास की एक पांडुलिपि तत्कालीन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की गई। उसमें एक वाक्य था, 'राजीव गांधी की हत्या तमिल क्रिश्चियन व्यक्ति द्वारा की गई।' एक पाठ का शीर्षक था, 'इस्लामिक कट्टरवाद।' यह सही है कि निदेशक एक शब्द भी लेखक की अनुमति के बिना बदल नहीं सकते, लेकिन वह पांडुलिपि को अस्वीकृत कर सकते हैं। तब भी ऐसा ही किया गया और नई पांडुलिपि तैयार की गई। एनसीईआरटी की पुस्तकों में परिवर्तन के सुझाव साल भर अध्यापकों, छात्रों, लेखकों तथा विद्वानों की ओर से आते रहते हैं। संस्था के विद्वान विशेषज्ञ उनका अध्ययन करते हैं, और जहां आवश्यक होता है परिवर्तन करते हैं। एनसीईआरटी की किताबें प्रति वर्ष मुद्रित होती हैं।

2001 में कक्षा तीन के एक विद्यार्थी ने पत्र लिख एक पुस्तक में प्रकाशित चित्र के शीर्षक पर सवाल उठाया। वह शीर्षक था- 'किसान हल जोत रहा है', जबकि किसान कंधे पर हल रखे हुए था। उसका संज्ञान लेते हुए अगले वर्ष पुस्तक में आवश्यक सुधार किए गए और उस छात्र को पत्र लिख गलती के लिए क्षमा मांगी गई। इससे साफ होता है कि एनसीईआरटी ने समय के साथ अपनी गलतियां सुधारी हैं, लेकिन हर संस्था के समक्ष यह संभावना नहीं रहती। जब एक स्तर पर न्यायालय से दोषी पाया गया युवक 15-20 साल बाद ऊंचे स्तर के न्यायालय से अपराध मुक्त कर दिया जाता है, तब उसके जीवन के साथ न्याय करना सर्वोच्च न्यायालय के बस में नहीं रह जाता। यह भारतीय संस्कृति की सर्वमान्य अवधारणा है कि अध्यापक को सदा ही संवेदनशील, अहंकार विहीन और ज्ञान अर्जन के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे जीवन-पर्यंत सीखते रहने के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर एनसीईआरटी को पिछले छह दशकों से विकसित किया जाता रहा है। यह सिद्धांत हर स्तर के न्यायालयों पर भी लागू होता है और होने चाहिए। देश के विकास के लिए संस्थाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और सम्मान ऐसे मूलभूत मानवीय मूल्य हैं, जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता।

जंग के कारण कच्चे तेल के दाम बेकाबू! क्या है जंग की असल कारण और कब रुकेगी जंग

डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की कीमतें 96।56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जो 6।23% (यानी 5।66 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि) के बराबर है। 10 मार्च को विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में 7% से अधिक की वृद्धि हुई।

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर जो जंग शुरू की थी, वह अब खतरनाक होती जा रही है। जंग का बदला लेने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला कर दिया। इस कारण कई देशों को हमले के डर से तेल का उत्पादन रोकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद से ये 42% ज्यादा है। भारत का कहना है कि उसके पास काफी रिजर्व है लेकिन लंबे समय तक कीमतों में उतार-चढ़ाव से आम घरों से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 फीसदी कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिससे कीमतें बढ़ने पर उसे सीधा नुकसान हो सकता है। कच्चे तेल की ज्यादा कीमतें महंगाई बढ़ा सकती हैं, व्यापार घाटा बढ़ा सकती हैं और घरों का बजट बिगाड़ सकती हैं, खासकर कुकिंग गैस के मामले में। सरकार ने पहले भी ऐसे झटकों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और अब फिर ऐसा ही कुछ करने की जरूरत आ गई है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी का पूरा बोझ आम लोगों पर डाला जाता है तो इससे महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ में 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी आएगी। यह इसलिए गंभीर है, क्योंकि खाड़ी देश एशिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। 2025 में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला 87% कच्चा तेल और 86 फीसदी LNG एशियाई देशों में ही आया। यह रास्ता अब बंद हो गया है। कुछ दिन पहले ही LPG की कीमत भी बढ़ा दी गई है, जो लगभग एक साल बाद पहली बढ़ोतरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LPG कंज्यूमर है और 90% से ज्यादा LPG मिडिल ईस्ट से आता है। केंद्र सरकार ने तेल के झटकों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले भी टैक्स में कटौती की है। 2022 में जब रूस-यूक्रेन जंग के बाद कच्चा तेल 116 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, ताकि कीमतें स्थिर रहें। इससे पहले 2008 में जब क्रूड 147 डॉलर पर आ गया था तो महंगाई को काबू में करने के लिए इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 97।60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जो 7।47% (यानी 6।92 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि) के बराबर है। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की कीमतें 96।56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जो 6। 23% (यानी 5।66 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि) के बराबर है। 10 मार्च को विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। शुरुआती कारोबार में, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें संक्षेप में बढ़कर 119। 50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं; डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 119। 48 डॉलर प्रति बैरल के शिखर पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार, ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि से वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इस चिंता के कारण बाजार ने अपने इंट्राडे उच्च स्तर से हुई बढ़त को सीमित कर दिया है। गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ शुरू हुए ईरान युद्ध को आज दस दिन हो गया है। इस युद्ध का असली खामियाजा अब सभी को भुगतना पड़ रहा है और इस युद्ध में पागलपन का भाव है। हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने ईरानी चुनौती को चुटकी में हल करने की कसम खाई है, अभी भी इस युद्ध की तबाही के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल कि उन्हें दो सरदारों की गैरजिम्मेदारी के लिए कितना और क्यों भुगतान करना चाहिए, अब वास्तविकता का संकेत बनता जा रहा है। यह भविष्य ईरान के बेड़े में तीन हजार से अधिक मिसाइलों में निहित है, जो ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के मामले से अधिक है, जिनमें से आधे से अधिक मध्यम से लंबी दूरी की हैं। 'फतेह', 'फतेह 300', 'खोरमशेर 400', 'खैबरशेक', 'हाजी कासिम', 'शहाब', 'इमाद' आदि इजराइल ने इन मिसाइलों की क्षमताओं का आकलन नहीं किया; लेकिन इससे भी अधिक, ट्रम्प ने इज़राइल के नरसंहार नेतन्याहू पर भरोसा करते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। भविष्य विशाल, अरबों डॉलर की रडार प्रणालियों में निहित है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व के विभिन्न केंद्रीय देशों में तैनात किया है, और भविष्य ड्रोन की मदद से इन अरबों डॉलर की प्रणालियों को नष्ट करने की ईरान की क्षमता में निहित है, और भविष्य हमारे जैसे अन्य देशों की लाचारी में निहित है जो दर्शक हैं भविष्य सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों में है, जिन्होंने सबसे पहले ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश की। ईरान ने इन देशों के भविष्य को अपने हाथ में ले लिया और सामने आया। जैसे-जैसे ये देश बने थे, शांति से रहने वाले लोग उन देशों को स्वर्ग मानते थे। ये देश, वास्तव में, व्यक्तिगत परिवारों की निजी संपत्ति हैं, और कई लोगों के हित उन संपत्तियों में शामिल हैं। इन देशों को 'प्रबंधित' करना आसान है। अमेरिका इतने सालों तक इन देशों को चुप रखने में कामयाब रहा है और इसी के दम पर अमेरिका इन सभी देशों को इतने सालों तक चुप रखने में सफल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के विजयी सेनानी जनरल आइजनहावर ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस मंत्र की शुरुआत की और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया, जो संगठन सभी इस्लामी आतंकवादियों की रीढ़ था संगठन के नेता, हसन अल-बन्ना, को व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया था, और इतने वर्षों तक इज़राइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इस्लामी मौलवियों को इशांतर करने के सौदे में एक दलाल के रूप में ईमानदारी से काम किया था, बदले में इजरायल को अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति देने के लिए, और निजी संपत्ति के मालिक इस्लामी देशों के प्रमुखों की रक्षा करने के लिए।

अशोक भाटिया

जन सुराज का...

सौरभ वार्ष्णेय

राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देती ?

भारत में जब किसी राज्य में कानून-व्यवस्था या राजनीतिक टकराव को लेकर विवाद बढ़ता है तो अक्सर यह सवाल उठता है कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को क्यों नहीं हटा देते? हाल के समय में भी पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर ऐसी चर्चाएँ सुनाई देती हैं लेकिन भारतीय संविधान में राज्य सरकार को बर्खास्त करना इतना सरल या मनमाना निर्णय नहीं है। इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया और ठोस कारण आवश्यक होते हैं। अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 7 मार्च, 2026) को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने गईं थीं जहां कई अव्यवस्थायें देखने को मिलीं जिसे लेकर राष्ट्रपति ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस पर विपक्ष का कहना था कि वहां चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं जबकि राष्ट्रपति का पद राजनीति से बहुत ऊपर है। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाना तो तय है। यह मुद्दा इतना गर्म हो गया था कि दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति जी के अपमान और संथाल संस्कृति के साथ किए गए लापरवाही भरे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो भी लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास करता है, वो इस घटना से बहुत निराश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी खुद आदिवासी समुदाय से हैं, और उन्होंने जो दर्द और पीड़ा व्यक्त की है उसने भारत के लोगों को बहुत दुःखी किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इतना लापरवाही भरा व्यवहार कर रही है। इस कार्यालय की पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी को सद्बुद्धि आएगी। अब ऐसे में भारत की राष्ट्रपति, वर्तमान में द्रोपदी मुर्मु, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। हालांकि वे अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय लेती हैं। किसी राज्य की सरकार को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आता है, जिसे आम तौर पर 'राष्ट्रपति शासन' कहा जाता है। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी कर रही हैं। यदि राज्य में राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक विफलता या अन्य गंभीर स्थिति की शिकायतें होती भी हैं, तब भी केवल आरोपों या राजनीतिक मतभेद के आधार पर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट, केंद्र सरकार का आकलन और अंततः संसद की मंजूरी जैसी प्रक्रियाएँ जरूरी होती हैं। इतिहास बताता है कि अनुच्छेद 356 का कई बार राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हुआ है। इसी कारण एसआर बोम्माई वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा और इसे मनमाने तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद राज्यों की चुनी हुई सरकारों को हटाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने का सबसे बड़ा अधिकार अंततः जनता के पास ही होता है। यदि किसी राज्य की सरकार से असंतोष है, तो उसका समाधान चुनाव के माध्यम से किया जाता है। इसलिए केवल राजनीतिक विवाद या आरोपों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे राज्य सरकार को बर्खास्त करना न तो संवैधानिक रूप से उचित है और न ही लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार को हटाने का सवाल केवल राजनीतिक इच्छा का नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का विषय है। जब तक यह साबित न हो जाए कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, तब तक किसी भी सरकार को बर्खास्त करना संभव नहीं होता। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराज़ होने की चर्चा मुख्यतः राज्य में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक टकराव और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों के कारण उठती रही है। हाल के समय में कुछ घटनाओं ने इस तनाव को और बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में कई बार राजनीतिक हिंसा, चुनावी टकराव और साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ सामने आती रही हैं।

गौर करने वाली...

जगराम गुर्जर

पारंपरिक मेलों पर संकटः सुरक्षा और आजीविका के बीच संतुलन की तलाश

भारत के पारंपरिक मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं. वे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का जीवंत हिस्सा हैं। गांव-गांव, शहर-शहर लगने वाले ये मेले सदियों से लोगों के मेल-मिलाप, लोक संस्कृति और आजीविका का आधार रहे हैं। यहां झूले लगाने वाले, खिलौने बेचने वाले, बर्तन, चूड़ी, हस्तशिल्प बेचने वाले दुकानदार, बुनकर, लोक कलाकार और छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों परिवार अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं लेकिन आज यह पारंपरिक कारोबार गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से गुजरात में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मेले लगभग समाप्ति की ओर हैं। अन्य राज्यों में भी कड़े नियमों की आशंका से मेला आयोजकों और झूला संचालकों के बीच असुरक्षा का माहौल है। राजकोट में एक गेमिंग जोन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस हादसे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त नियम लागू किए। जन सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन नियम बनाते समय इस बात पर शायद ध्यान ही नहीं दिया गया कि राजकोट की घटना एक बंद, पक्के और अवैध गेमिंग जोन में हुई थी जबकि पारंपरिक मेले और झूले खुले वातावरण में अस्थायी ढांचे में लगाए जाते हैं। खुले मेलों के झूले न तो पक्के भवनों में होते हैं, न ही उनमें जटिल बिजली व्यवस्था या आग पकडने वाली बनावट होती हैं। इसके बावजूद नए नियमों का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं छोटे मेला आयोजकों और झूला संचालकों पर पड़ा है। नए प्रावधानों के तहत महंगे इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, भारी बीमा कवर, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया और बार-बार निरीक्षण जैसी शर्तें लागू कर दी गई हैं। छोटे स्तर पर काम करने वाले ये लोग पहले ही भारी कर्ज लेकर अपने झूले खरीदते हैं। उनके लिए महंगे प्रमाण पत्र और बीमा प्रीमियम जुटाना लगभग असंभव है। परिणामस्वरूप, गुजरात में मेले लगने बंद हो गए हैं, झूले खुले मैदानों में जंग खा रहे हैं और हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मेले और झूले वालों में से अधिकांश के पास इस पारंपरिक काम के अलावा कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है। पीढ़ियों से यही इनका पेशा रहा है। यह केवल व्यवसाय नहीं, इनकी पहचान भी है। यदि यह बंद होता है तो केवल रोजगार ही नहीं, एक जीवंत लोक परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। गौर करने वाली बात है कि कोई भी मेला आयोजक या झूला संचालक सुरक्षा नियमों को हटाने की मांग नहीं कर रहा। बंद गेमिंग जोनों के लिए कठोर नियम आवश्यक हैं और उनका पालन होना चाहिए लेकिन खुले मेलों के पारंपरिक झूलों के लिए अलग, सरल और व्यवहारिक नियम बनाए जाने चाहिए। सरकार यदि श्रेणीकरण (कैटेगराइजेशन) की व्यवस्था करे तो भी झूले वालों को राहत मिल सकती है। जैसे बड़े यांत्रिक राइड्स और छोटे पारंपरिक झूलों के लिए अलग-अलग मानक बनाए जाएं तो इससे संतुलन बन सकता है। इसके साथ ही समूह बीमा योजना, कम लागत निरीक्षण प्रणाली और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम उठाए जाएं तो मेला व्यवसायी सुरक्षा मानकों का पालन भी कर सकेंगे और अपनी आजीविका भी बचा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है।

जरा हटके

इस जीत का एक ...

घनश्याम बादल

जीत की रीत का नया गीत

देश और क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी 20 वर्ल्ड कप का तोहफा देश को दिया है। इतिहास और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए फाइनल से पहले जिस तरह सबकी दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी वह इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इससे पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हर बार हार का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड से टी 20 वर्ल्ड कप में हर बार हार मिली थी और कोई भी टीम लगातार दो बार टूर्नामेंट जीत कर खिताब नहीं बचा पाई थी साथ ही साथ अब तक किसी भी देश ने तीन बार टी 20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था लेकिन चुनौतियों और उतार-चढ़ाव से पर पाते हुए इस भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। टी-20 विश्व कप पर लगातार दूसरी बार कब्जा केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सामूहिक प्रतिभा, धैर्य, रणनीति और संघर्ष की अद्भुत गाथा है। यह जीत उस लंबे सफर का परिणाम है जिसमें कठिन चुनौतियाँ, विवाद, हार-जीत के उतार-चढ़ाव और खिलाड़ियों की अथक मेहनत शामिल रही। इस विश्व कप का सफर आसान नहीं था। टूर्नामेंट से पहले ही उपमहाद्वीप की राजनीति का असर खेल पर दिखाई दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े विवादों तथा विभिन्न कूटनीतिक तनावों ने प्रतियोगिता का मज़ा किरकिरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी । ऐसे में भारतीय टीम को न केवल मैदान पर बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित रहना पड़ा। प्रतियोगिता के दौरान स्टीम ने अपने ग्रुप के दूसरे सारे मैच जीते लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने बड़ा झटका दिया। बेशक उस टीम का आत्मविश्वास डगम गया होगा. डटकर आलोचना भी हुई कोच और कप्तान ने भी कड़ा रुख अपनाया लेकिन सच कहें तो उसी मैच ने यह संकेत दिया कि भारतीय टीम अजेय नहीं है और यदि रणनीति में ढिलाई बरती तो विरोधी टीमें अवसर का लाभ उठा सकती हैं। महान टीमों की पहचान होती है कि वे हार से टूटती नहीं बल्कि सीखती हैं। भारत ने भी यही किया,णनीति बदली, संयोजन सुधारा और लगातार असफल हो रहे अभिषेक और मौके पर पटरी से उतरी गेंदबाजी कर रहे वरुण चक्रवर्ती पर विश्वास जताया, अगले मैचों में और अधिक आक्रामक रूप में मैदान में उतरी और एक चोट ने सारा नज़ारा बदल दिया. परिणाम सामने है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबला इस विश्व कप का सबसे निर्णायक मोड़ था। इंग्लैंड की टीम आक्रामक बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी डरा देने वाली थी, इसलिए यह मैच भारत की वास्तविक परीक्षा था। भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव को अवसर में बदल बड़े स्कोर का पहाड़ खड़ा किया। अप्रत्याशित रूप से बिना दबाव के विस्फोटक तरीके से खेल रहे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजों ने अंतिम क्षणों में संयम और रणनीति के साथ इंग्लैंड की चुनौती को विफल कर फाइनल में प्रवेश किया । फाइनल में मिली एक तरफा धमाकेदार जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम केवल किसी एक की प्रतिभा से नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास और परिपक्वता से लैस है। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि पूरी टीम की थी।शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत देकर टीम को मजबूत आधार दिया। तो मध्यक्रम ने उसे गति को बनाए रखा,ऑल-राउंडरों ने बल्ले और गेंद दोनों से निर्णायक भूमिका निभाई। जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर विपक्षी टीम को दबाव में रखा, जबकि स्पिनर अक्षर पटेल ने मध्य ओवरों में मैच की दिशा बदल दी। हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया तो शिवम दुबे ने विस्फोटक परी खेड़ी अब संजू सैमसन तो पूरी प्रतियोगिता में ही तारणहार बने शिवम दुबे, ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मौका मिलते ही अपना काम किया । फ़ाइनल में अभिषेक का जलवा उनकी पिछली विफलताओं को भुला गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्ले से भले ही नहीं चल पाए लेकिन उनकी रणनीति पूरे टूर्नामेंट में विपक्षियों की समझ से बाहर रही। कुल मिलाकर टीम के इस प्रदर्शन को अद्भुत, अप्रतिम और शानदार ही कहा जाएगा। कुछ कमियों के बावजूद फील्डिंग भी भारतीय ताकत बनकर उभरी. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा के कैच लंबे समय तक याद किए जाएंगे। इस जीत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि भारतीय क्रिकेट अब केवल कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रही। नई पीढ़ी के खिलाड़ी, युवा बल्लेबाज, तेज गेंदबाज और बहुमुखी ऑल-राउंडर अब जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। यह पीढ़ी तकनीक, फिटनेस और मानसिक दृढ़ता के मामले में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। यही कारण है कि भारतीय टीम कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने में सफल र इस जीत से छोटे शहरों और गांवों से आने वाले लाखों युवाओं को विश्वास मिलेगा कि मेहनत और प्रतिभा से विश्व मंच पर पहुँचना संभव है।खेल अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, क्रिकेट की सफलता खेल उद्योग, प्रसारण, प्रायोजन और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। यह जीत जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह देखना है कि देश इस उपलब्धि को खेल संस्कृति के व्यापक विकास में कैसे बदलता है। शिक्षा व्यवस्था में खेलों को अनिवार्य और व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। हर जिले में आधुनिक खेल मैदान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ तो यह जीत और भी असरकारी हो जाएगी। बेशक, भारत में क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन, तीरंदाजी और कबड्डी जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों में भी अपार संभावनाएँ हैं। यदि इन खेलों को भी संरचना और संसाधन मिलें, तो भारत बहु-खेल महाशक्ति बन सकता है। देश की वास्तविक प्रतिभा गांवों और छोटे कस्बों में छिपी है। वहाँ से खिलाड़ियों को खोजने और प्रशिक्षित करने की व्यावहारिक और असरदार राष्ट्रीय स्तर की योजना बननी चाहिए। आधुनिक खेलों में फिटनेस, पोषण, डेटा विश्लेषण और खेल विज्ञान की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत को इन क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाना होगा। भारतीय टीम की यह ऐतिहासिक जीत केवल क्रिकेट का गौरव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विजय को केवल उत्सव तक सीमित न रख, ऐसी खेल संस्कृति के निर्माण का आधार बनाया जाए जिसमें हर बच्चा मैदान तक पहुँचे, हर प्रतिभा को अवसर मिले और भारत विश्व खेल मंच पर हर क्षेत्र में चमकता दिखाई दे।

टीम इंडिया को 131 करोड़ देगा बीसीसीआई

खिलाड़ियों, स्टाफ और सिलेक्टर्स को बधाई दी, भारत तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन

ऐलान

अहमदाबाद, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 जीतने पर 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है। भारत ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद BCCI ने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि की सराहना की है। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। पूरे मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जिससे टीम को यादगार जीत हासिल हुई।

टी-20 विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अब तक दो-दो बार यह खिताब जीता है। वहीं भारत अब तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया है, जिससे वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बनकर उभरा है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रशंसक सोशल मीडिया और सड़कों पर टीम इंडिया की जीत का उत्सव मना रहे हैं।

भारतीय टीम को 27.5 करोड़ प्राइजल मनी मिली

रिपोर्ट के मुताबिक, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम को 3 मिलियन डॉलर (करीब 27.5 करोड़ रुपए) की इनामी राशि मिली। वहीं, रनर-अप न्यूजीलैंड को 1.6 मिलियन डॉलर (करीब 14.7 करोड़ रुपए) दिए गए। हालांकि, इस बार ICC ने प्राइज मनी की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, जबकि आमतौर पर हर टूर्नामेंट में इसकी जानकारी पहले ही दे दी जाती है।

भारत 3 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहला देश

भारतीय टीम 2024 के बाद 2026 में भी चैंपियन बनी और टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई। इसके साथ ही इंडिया तीन टी-20 वर्ल्ड कप (2007, 2024 और 2026) जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन गया।

सूर्या का 500 साल पुरानी बावड़ी में फोटोशूट

टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के जश्न के अलग-अलग अंदाज देखने को मिले। कप्तान सूर्यकुमार यादव गुजरात के गांधीनगर स्थित 500 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी अडालज नी वाव में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करते नजर आए। वहीं क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया स्वर्णिम अध्याय साबित होगी।

भारत के नाम अब तीन टी-20 वर्ल्ड कप

इस जीत के साथ भारत के नाम अब टी-20 विश्व कप की कुल तीन ट्रॉफियां हो गई हैं। भारत ने पहला खिताब आईसीसी टी-20 विश्व कप 2007 में जीता था, जब टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इसके बाद दूसरा खिताब आईसीसी टी-20 विश्व कप 2024 में वेस्टइंडीज में जीता गया था।

बीसीसीआई ने जताया गर्व

BCCI ने अपनी घोषणा में कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और फाइनल में दबाव के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया। बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, टीमवर्क और कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि भारत ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की।

मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के नए बैटिंग कोच बने

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर 2026 सीजन के लिए टीम से जुड़े

भोपाल, एजेंसी

IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी कोचिंग टीम में बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया। हेडन दो बार के वनडे वर्ल्ड कप विजेता हैं और अपने जमाने के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। हेडन की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब टीम अपनी बैटिंग यूनिट को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। विक्रम सोलंकी बोले- हेडन के आने से युवाओं को फायदा होगा फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी ने कहा कि हेडन का अनुभव टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हेडन की नियुक्ति

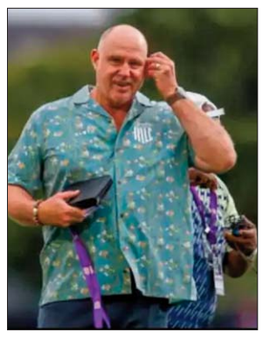

पर बात करते हुए सोलंकी ने कहा,'मैथ्यू हेडन का हमारी टीम से जुड़ना एक अहम पड़ाव है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो अनुभव रहा है और युवाओं को निखारने की जो उनकी काबिलियत है, उससे हमारी टीम को अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले सीजन के लिए वह हमारी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करेंगे।'

पांच ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने शरण दी

कैनबरा। ईरान की महिला फुटबॉल टीम की पांच खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय आधार पर वीजा जारी कर अपने देश में रहने की अनुमति दे दी है। यह फैसला उस समय लिया गया जब खिलाड़ियों ने संभावित कार्रवाई के डर से ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी थी। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मंत्री टोनी बर्क ने बताया कि इन खिलाड़ियों को पुलिस की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। दरअसल, पिछले सप्ताह ईरान महिला फुटबॉल टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ एशियन कप मैच से पहले राष्ट्रगान नहीं गाया था। इस घटना के बाद ईरान में कुछ लोगों ने टीम की कड़ी आलोचना की और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। स्थिति को देखते हुए टीम की कुछ खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि टीम में कुल 26 खिलाड़ी और स्टाफ मौजूद थे, लेकिन फिलहाल केवल पांच खिलाड़ियों ने ही शरण मांगी है। बाकी खिलाड़ी अभी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

फास्ट न्यूज

एक्टर रणदीप हुड्डा पिता बने

सोनीपत। हरियाणा के रहने वाले बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी लिन लैशराम ने बेटी को जन्म दिया। रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। रणदीप के पिता रणवीर हुड्डा का भी आज ही जन्मदिन है। रणदीप ने अपने पिता और बेटी की फोटो शेयर करते हुए हरियाणवी में लिखा, दादा अर पोती नै जन्मदिन की घणिए बधाई।

ईरान-इजराइल तनाव से चीन को झटका

बीजिंग/मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध चीन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल चीन ने मिडिल ईस्ट में भारी निवेश किया हुआ है। साथ ही ये क्षेत्र उसके इस्पात, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों के लिए बड़ा बाजार है। ईरान के रूप में चीन को तेल का सस्ता स्रोत मिला था। पूरे क्षेत्र में उसे ऐसी सरकारें भी मिलीं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में चीन से सीखने के लिए उत्सुक थीं। इन्हीं सब के बीच चीन तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व की आपूर्ति पर निर्भर हो गया। जब पिछले साल अमेरिका से चीन की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी तो वह अमेरिकी बाजार में अपने कई सामान बेचने में असमर्थ रहा, जो कभी चीन का सबसे बड़ा बाजार था। इसके बाद चीन के लिए मिडिल ईस्ट का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया था।

56 जातीय समूहों को एक पहचान मिलेगी

बीजिंग। चीन में जिनपिंग सरकार एक नए कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जिसमें अलग-अलग जातीय समूहों (एथनिक ग्रुप्स) को एक ही राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का नाम 'लॉ ऑन प्रोमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस' है। चीन में हान, उइगुर, तिब्बती, मंगोल जैसे 56 जातीय समूह हैं। चीन की सरकार पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं।

शादी के बाद इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना

बोलीं- ऐसा प्यार ढूंढो जो आपको आजाद कर दे

मुंबई, एजेंसी

साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक सोशल मीडिया नोट को पढ़कर भावुक हो गईं। ये नोट रश्मिका और विजय देवरकोंडा के प्यार पर लिखा गया था। एक्ट्रेस ने X पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए बताया कि इस नोट ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने फैंस को सलाह भी दी कि जीवन में ऐसा प्यार तलाशें जो आपको बंधन में नहीं, बल्कि आजादी का अहसास कराए। 9 मार्च को एक फैन ने विजय और रश्मिका की शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें इस 'स्वार्थी युग' में सच्चे प्यार की मिसाल बताया था। नोट में लिखा था कि रश्मिका जिस तरह से विजय को देखती हैं, वह प्रशंसा और प्यार का सबसे ईमानदार सबूत है। इसे पढ़कर रश्मिका खुद को रोक नहीं पाईं और माना कि लंबे समय बाद किसी बात ने उन्हें इतना इमोशनल किया है।

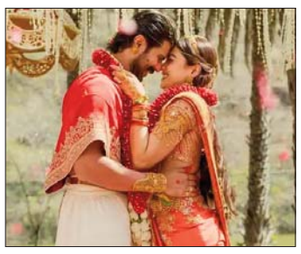

एक्ट्रेस ने भावुक होकर लिखा, मेरे बारे में लिखी गई किसी चीज ने मुझे लंबे समय बाद इतना प्रभावित नहीं किया। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं अपनी जगह तलाश रही हूं और इस सफर के लिए आभारी हूं। प्यार के बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि उस प्यार को ढूंढो, जो तुम्हें आजाद कर दे। एक्ट्रेस ने उस यूजर का शुक्रिया भी अदा किया जिसने उनके और विजय के रिश्ते की गहराई को इतनी खूबसूरती से पहचाना।

फ्लाइट में बैठते ही घबराईं, आंखों में आए आंसू, सुरक्षित भारत पहुंचकर फैंस को दिया अपडेट

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कुवैत से भारत लौटीं उर्वशी

मुंबई/कुवैत, एजेंसी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला जल्दबाजी में कुवैत से भारत लौट आई हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बताया कि वहां के हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए थे, जिससे वह काफी घबरा गई थीं और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल, हाल के दिनों में ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई जगहों से मिसाइल हमलों और हाई अलर्ट की खबरें सामने आ रही हैं। इसी दौरान उर्वशी रौतेला अपने एक प्रोफेशनल काम के सिलसिले में

कुवैत गई हुई थीं, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उन्होंने तुरंत वहां से वापस लौटने का फैसला किया। इसी दौरान उर्वशी रौतेला भी भावुक हो गईं और फ्लाइट में सवार होने से पहले उनकी आंखों से आंसू निकल आए। एयरपोर्ट पर मौजूद कई यात्रियों ने भी स्थिति को चिंताजनक बताया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय कुवैत एयरपोर्ट पर माहौल काफी तनावपूर्ण था। कई विदेशी नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई थी और यात्रियों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।

फ्लाइट में बैठने के बाद अचानक बढ़ी घबराहट

उर्वशी रौतेला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उस पल का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब तक वह फ्लाइट में बैठीं, तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सीट पर बैठते ही उन्हें अचानक घबराहट महसूस होने लगी। एक्ट्रेस ने लिखा कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और डर की भावना ने उन्हें घेर लिया। उस समय वह खुद को असुरक्षित और चिंतित महसूस कर रही थीं। उन्होंने अपने फैंस से उनके लिए दुआ करने की अपील भी की।

सुरक्षित भारत पहुंचने के बाद फैंस को दी जानकारी

हालांकि राहत की बात यह है कि उर्वशी अब सुरक्षित भारत पहुंच चुकी हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक्ट्रेस ने स्थानीय प्रशासन और एयरपोर्ट स्टाफ का भी धन्यवाद किया।

90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहां से, एक्सपर्ट बोले- इस पर हमले से विश्वयुद्ध का खतरा

ट्रम्प ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं

दावा

तेहरान, एजेंसी

अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद खार्ग आइलैंड की अहमियत अचानक बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रम्प सरकार इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि यह ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है।

दरअसल ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी आइलैंड से होता है। यहां बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद हैं। इसे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। खार्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है।

यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनल को तबाह कर दिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए, तो ईरान की सबसे बड़ी आय बंद हो सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा ईरान की सरकार और उसकी सैन्य ताकत के लिए सबसे बड़ा आर्थिक सहारा है।

डार्क फ्लीट से भेजा जा रहा तेल

ईरान कई बार ऐसे टैंकरों का इस्तेमाल करता है जिन्हें डार्क फ्लीट कहा जाता है। ये जहाज अपनी लोकेशन दिखाने वाली ट्रैकिंग मशीन बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। हाल ही में एक बड़ा तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार करते समय कुछ समय के लिए ट्रैकिंग से गायब हो गया था और बाद में फिर दिखाई दिया।

जंग के बीच भी जारी है तेल निर्यात

अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है, लेकिन खार्ग आइलैंड पर अब तक हमला नहीं हुआ है। सैटेलाइट डेटा और जहाजों की निगरानी करने वाली कंपनियों के मुताबिक जंग जारी होने के बावजूद ईरान यहां से लगातार तेल निर्यात कर रहा है।

1960 के दशक में विदेशी निवेश के बाद इस जगह को बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया था और तब से यह ईरान की ऑयल सप्लाई की रीढ़ बन गया। हडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल डोरान ने कहा, ट्रम्प सरकार युद्ध के बाद भी ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह नहीं करना चाहती है। अमेरिका की पुरानी 'रेड लाइन' यानी तय सीमा यह रही है कि कुछ खास और अहम ठिकानों पर हमला नहीं किया जाए।

खामेनेई की तस्वीर लेकर सड़कों पर रोती महिलाएं

दो साल की बच्ची के जनाजे में पहुंचे हजारों लोग

- ईरान में एयरस्ट्राइक में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शोक मनाने शामिल हुए लोग।
- ईरान के मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हमले के बाद पीड़ितों के अंतिम संस्कार में लोग शामिल हुए।
- जैनब साहेबी को कंधा देते वक्त कई महिलाएं फूट-फूटकर रो रही थीं।

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है। जंग के पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ईरान में महिलाओं सहित हजारों लोग सड़कों पर उतरे और

नारेबाजी की और सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि दी। उधर, युद्ध का असर पूरे मिडिल ईस्ट और उससे जुड़े देशों में दिखाई दे रहा है। बीते 10 दिनों में इस संघर्ष ने 10 से ज्यादा देशों के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है, कहीं बमबारी, कहीं विरोध प्रदर्शन और कहीं भय का माहौल है।

परेशानी गैस नहीं मिलने से होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत, जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद

नई दिल्ली, एजेंसी

अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में LPG की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। ऐसे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि तेल कंपनियां अलग-अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशनों से बात करेंगी, ताकि LPG सप्लाई की दिक्कतों को समझा जा सके। इधर, केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोक ने लिए देशभर में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' लागू कर दिया है। अब गैस को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा.ब कभी किसी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है।

- **पहली कैटेगरी (पूरी सप्लाई):** इसमें घर की रसोई गैस (PNG) और गाड़ियों में डलने वाली CNG आती है। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी।
- **दूसरी कैटेगरी (खाद कारखाने):** खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है।
- **तीसरी कैटेगरी (बड़े उद्योग):** नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी।
- **चौथी कैटेगरी (छोटे बिजनेस और होटल):** शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी।

महाराष्ट्र: मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद

मुंबई, पुणे और नागपुर में कॉमर्शियल गैस की भारी कटौती की गई है। पुणे में तो हालात इतने खराब हैं कि नगर निगम ने गैस शवदाह गृह अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। राज्य के करीब 9,000 रेस्टोरेंट्स और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में कॉमर्शियल गैस सप्लाई की किल्लत की वजह से अब तक करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। होटल एसोसिएशन 'आहार' (AHAR) ने चेतावनी दी है।

राजस्थान: होटल-रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन से जुड़े लोगों को परेशानी

यहां होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में हर तरह के होटल-रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों को बड़ी परेशानी होनी तय है। ज्यादा यानी 50% होटलों पर ताले लग सकते हैं।

कर्नाटक: होटल भी 'जरूरी सेवा', बंद होने से बुजुर्गों-छात्रों को दिक्कत

बेंगलुरु होटल एसोसिएशन का कहना है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई होटल बंद करने पड़ेंगे। मुंबई में कॉमर्शियल गैस सप्लाई की किल्लत की वजह से अब तक करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं।

क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम?

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एक ऐसा कानून है, जो सरकार को यह ताकत देता है कि वह किसी भी जरूरी चीज जैसे- अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके।

इसे आसान भाषा में 'जमाखोरी रोकने वाला कानून' कह सकते हैं।

राजनीति और टैक्स से परेशान अरबपति छोड़ रहे अपना देश

लंदन/ वॉशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों के बीच इन दिनों अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसने की लहर सी चल रही है। विशेषज्ञ इसे इतिहास का 'सबसे बड़ा निजी संपत्ति प्रवास' बता रहे हैं। कभी टैक्स लाभ की तलाश में होने वाला यह पलायन अब 'रक्षात्मक' हो गया है। अमीर अब अपनी संपत्ति बचाने, पीढ़ियों की सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए 'गोल्डन वीसा' और विदेशी नागरिकता का सहारा ले रहे हैं। स्विस बैंक यूबीएस ने अपने 87 अरबपति ग्राहकों के सर्वेक्षण में पाया कि 2025 में 36% अरबपति कम से कम एक बार अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, जबकि 9% अन्य इस पर विचार कर रहे हैं। विशेष रूप से 54 वर्ष से कम उम्र के 44% युवा अरबपति पिछले साल दूसरे देश शिफ्ट हुए हैं। निवेश प्रवास फर्म 'हेनली एंड पार्टनर्स' के पास साल-दर-साल आवेदनों में 28% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। हेनले एंड पार्टनर्स की 'प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट' के मुताबिक 2018 में जहां करीब 1.08 लाख अरबपतियों ने देश बदला था।

घोषणा पत्र प्रपत्र 4 (नियम 8 देखें)

प्रकाशन स्थान	– तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
प्रकाशन अवधि	– दैनिक
मुद्रक का नाम	– विद्या देवी
(क्या भारत के नागरिक हैं)	– हाँ
(क्या विदेशी तो मूल देश)	– लागू नहीं
पता	– तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
प्रकाशक का नाम	– विद्या देवी
(क्या भारत के नागरिक हैं)	– हाँ
(क्या विदेशी तो मूल देश)	– लागू नहीं
पता	– तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
सम्पादक का नाम	– विद्यादेवी
(क्या भारत के नागरिक हैं)	– हाँ
(क्या विदेशी तो मूल देश)	– लागू नहीं
पता	– तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो	तमसा संकेत समाचार पत्र के स्वामी हैं जो समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं विद्यादेवी एत्दद्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

ह. विद्या देवी
मुद्रक एवं प्रकाशक
तमसा संकेत भवन शहजादपुर,
अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

दिनांक 11.03.2025

26 शर्तों के साथ अनुमति मिली, धर्म-जाति पर भड़काऊ भाषण दिया तो परमिशन रद्द होगी

लखनऊ पहुंचे शंकराचार्य, आज से गो-प्रतिष्ठा अभियान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज, मंगलवार को लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी में बैठकर हनुमान सेतु पर हनुमान जी के दर्शन किए। फिर स्मृति उपवन के लिए रवाना हो गए। वह कल यानी 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरूआत करेंगे। कार्यक्रम को 26 शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है। इनका उल्लंघन करने पर अनुमति रद्द मानी जाएगी। सोमवार देर रात अफसरों की बैठक के बाद अनुमति दी गई। बैठक में पुलिस के आला अफसर और LDA स्मारक समिति के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम आशियाना में पासी किला चौराहे के पास सांस्कृतिक स्थल पर

होना प्रस्तावित है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आशियाना, पीजीआई और कृष्णानगर थाने की फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। आयोजन स्थल पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, आयोजकों की ओर से 3 दिन के कार्यक्रम के लिए करीब 4.50 लाख रुपए शुल्क स्मारक समिति को जमा किया गया था।

आशियाना में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग

आयोजकों के मुताबिक, 11 मार्च को शीतला अष्टमी के अवसर पर आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा पर दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 'गो-प्रविष्ठा धर्मयुद्ध' का औपचारिक शंखनाद करेंगे और समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संत-समाज, विभिन्न संगठनों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

इन 26 शर्तों के साथ मिली है अनुमति

- धर्म, जाति, संप्रदाय व भाषा के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं होगा।
- किसी राजनीतिक/धार्मिक व्यक्ति पर अमर्यादित या विद्वेषपूर्ण भाषा नहीं होगी।
- नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे।
- सीमित संख्या में वाहनों का प्रवेश, यातायात बाधित नहीं होगा।
- पारंपरिक ध्वजदंड के अलावा घातक वस्तु नहीं ला सकेंगे।
- मांगों का ज्ञापन सक्षम अधिकारी को सौंपा जाएगा।
- किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
- लगाए गए पुलिस बल का भुगतान आयोजक करेंगे।
- शांत क्षेत्र में ढोल, संगीत और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे।
- यातायात और अग्निशमन विभाग के निर्देशों का पालन अनिवार्य।
- आवश्यक विभागीय अनुमति आयोजक स्वयं प्राप्त करेंगे।
- सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर वाहन पार्किंग नहीं होगी।
- ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के मानकों का पालन होगा।
- नियम उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय।
- अन्य आवश्यक अनुमति/लाइसेंस से छूट नहीं होगी।
- पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा (अधिकतम 75 डेसीबल) से अधिक नहीं होगा।
- आतिशबाजी, हथियार व हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित।
- पंडाल की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर होगी।
- पर्याप्त निजी सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे, अव्यवस्था नहीं होगी।
- सांप्रदायिक/जातीय टिप्पणी या उत्तेजक बयान नहीं होगा।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण बंद रहेगा।
- स्थान किराया व अन्य शुल्क आयोजक स्वयं देंगे।
- कोविड-19 गाइडलाइन का पालन होगा।
- जुलूस या शोभायात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- किसी शर्त के उल्लंघन पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

लखनऊ नगर आयुक्त के ऑफिस की कुर्की, इनवर्टर-सोफा बाहर निकाला

अफसर के फोन करने पर भी नहीं माने, 2.17 लाख बकाया

- लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में कुर्की करने के लिए पहुंचे टीम में संस्था के वकील और पदाधिकारी सामान बाहर निकालते।
- कुर्की की कार्रवाई को पूरा करने के लिए पुलिस बल नगर आयुक्त के कार्यालय में पहुंचा।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम मंगलवार को कुर्की करने पहुंची। इस पर नगर निगम कार्यालय में अफरा-तफरी की स्थिति हो गई। अधिकारियों के साथ में कर्मचारियों तक के हाथ-पांव फूल गए। सिविल कोर्ट के आदेश पर कुर्क अमीन और पुलिस की टीम नगर आयुक्त

ऑफिस पहुंची। कुर्सी-सोफे और इनवर्टर निकाल कर ले जाने लगी। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार के फोन पर बात करने और आश्वासन देने के बाद भी मामला नहीं संभला। आलाधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिस पर करीब 1 घंटे बाद कुर्की करने आई टीम वापस लौटी। एक दिन पहले ही मामले में कुर्की का नोटिस अपर नगर आयुक्त ललित कुमार के पास में आया था। बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारी स्थिति नहीं संभाल सके। दरअसल, मैसर्स गंगा संस्थान और नगर निगम के बीच में एक विवाद चल रहा है। गंगा संस्थान के वकील विवेक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ एक ऑर्डर दिया था। इसमें 2,17,000 रुपए का भुगतान नगर निगम को गंगा संस्थान को करने का आदेश दिया है। फर्म कैसरबाग में शेल्टर होम चला रही थी। मैसर्स गंगा संस्थान कैसरबाग में 2019 में सेल्टर होम का संचालन करता था। नगर निगम ने दिसंबर 2019 में संस्था को बताया कि शेल्टर होम संचालन की अनुमति सितम्बर 2019 में रद्द कर दी गई है। संस्थान ने सितम्बर से दिसबंर 2019 तक 3 महीने का सेल्टर होम संचालन में खर्च की गई राशि का भुगतान मांगा। नगर निगम ने भुगतान करने से मना कर दिया। नगर निगम के मना करने पर सिविल कोर्ट में बकाया राशि भुगतान के लिए वाद दायर किया। कोर्ट ने उनके फेवर में 2.17 लाख की डिक्री पारित की। उसी डिक्री के तहत आज टीम कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची थी।

फास्ट न्यूज

गैस सिलेंडर न मिलने पर हंगामा

लखनऊ। लखनऊ में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। लालबाग स्थित सहकारी गैस सर्विस वाला कदर रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर लोग सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं। घंटों इंतजार करने पर भी सिलेंडर न मिलने पर एक उपभोक्ता नाराज हो गया। उसने एजेंसीकर्मी से विरोध जताया तो उसकी पासबुक फाड़ दी गई।

नेशनल हाईवे पर 2किमी लंबा जाम

आगरा। आगरा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मंगलवार सुबह रामबाग फ्लाईओवर के आगे जवाहर पुल पर एक ट्रक खराब होने से हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम इतना भीषण था कि वाहन घंटों तक सड़क पर रेंगते रहे और कई लोग ऑफिस पहुंचने में देर से पहुंचे। जाम के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों को उठानी पड़ी। कई बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन जाम में फंसने के कारण समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल वैन से बीच रास्ते में उतारकर बाइक और स्कूटी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामबाग फ्लाईओवर और आसपास के इलाके में अक्सर जाम की स्थिति बनती रहती है।

कानपुर का गंगा मेला-सपा विधायक जमकर नाचे

कानपुर। आज मंगलवार को कानपुर में गंगा मेला है, होली खेली गई। रंगों में सराबोर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने लोगों के साथ जमकर डांस किया। मेस्टन रोड में मुस्लिमों ने हिंदुओं का फूल बरसाकर स्वागत किया। माला भी पहनाई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ऊंट पर सवार होकर हुरियारे निकले। जमकर रंग-गुलाल बरसा।

व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से की मुलाकात

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री से मंगलवार को पार्टी कार्यालय में मेरठ के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतुल प्रधान, विधायक मेरठ ने किया। व्यापारियों ने अखिलेश यादव से पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई और लाखों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़े इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट से जुड़े हजारों व्यापारी, मजदूर और उनके परिवार पिछले कई दिनों से अपनी आजीविका बचाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल दुकानों का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य और लाखों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि

आंदोलन के दौरान प्रशासन और पुलिस का रवैया बेहद सख्त रहा। उनका कहना था कि पुलिस लगातार टकराव का माहौल बनाने का प्रयास करती रही। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार हालात उस समय और गंभीर हो गए जब देर रात करीब 2 बजे लगभग 250 पुलिसकर्मी धरना स्थल पर पहुंचे, जबकि उस समय वहां केवल करीब 20 लोग ही मौजूद थे। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस ने टेंट हटाने, धरना समाप्त कराने और लोगों को डराने-धमकाने की कार्रवाई की। अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालकर उनकी मदद की जाएगी।

ईरान पर हमले के विरोध में लखनऊ में वामपंथी दलों का मार्च

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों के विरोध में मंगलवार को वामपंथी दलों ने संयुक्त रूप से विरोध मार्च निकाला। यह मार्च परिवर्तन चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। इस विरोध मार्च में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मार्च के दौरान वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और किसी भी देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साम्राज्यवादी ताकतें लंबे समय से तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित

करने के लिए विभिन्न देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करती रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि वेनेजुएला और ईरान से जुड़ी हालिया घटनाएं इसी नीति का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कथित अपहरण और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या जैसी घटनाएं वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। वामपंथी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर भारत सरकार के रुख की भी आलोचना की और कहा कि देश को स्वतंत्र और सिद्धांत आधारित विदेश नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार अमेरिकी–इज़राइली सैन्य कार्रवाई का स्पष्ट विरोध करे। रमेश सिंह सेंगर, जिला प्रभारी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेशन ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा युद्ध साम्राज्यवादी आक्रमण का एक और उदाहरण है। उनका कहना था कि तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संप्रभु देशों को निशाना बनाया जा रहा है। मधु गर्ग, जिला सचिव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने कहा कि ईरान पर हमला केवल एक देश के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा है। वहीं रिजवान, जिला कमेटी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि इराक, लीबिया, वेनेजुएला और अब ईरान की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी शक्तियां सैन्य ताकत के जरिए दुनिया के देशों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं।

ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख चौथी बार फिक्स

13 मार्च को रक्षामंत्री राजनाथ और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर फेज-2 की उद्घाटन की तारीख आखिरकार तय हो गई है। 13 मार्च को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम झूलेलाल पार्क में रखा गया है। यहां जनसभा होगी। उसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

इससे पहले उद्घाटन का समय 3 बार कैंसिल हो चुका है। पहले 22 फरवरी और बाद में 28 फरवरी की डेट तय हुई थी। एक डेट सार्वजनिक नहीं हुई थी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के एक साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। यह कॉरिडोर गोमतीनगर के समतामूलक चौक से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु और डालीगंज तक फैला है। इसके शुरू होने से शहर के करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो

चुका है, लेकिन औपचारिक उद्घाटन से पहले तक कॉरिडोर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कंक्रीट डिवाइडर लगाकर रास्ता बंद रखा गया है।

ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण निशातगंज से शुरू होकर गोमती नदी के किनारे-किनारे शहीद पथ तक जाएगा। इससे गोमती नगर विस्तार और आसपास के इलाकों के ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस फेज के निर्माण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। परियोजना का तीसरा चरण शहीद पथ को बाहरी रिंग रोड यानी किसान पथ से जोड़ेगा।

कानपुर में आरोपी बोला- मारना नहीं चाहता था, उसने बहन से मिलते देख लिया था भांजी से प्रेम छिपाने के लिए भांजे का गला घोंटा

हत्या

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। "मैं अहमदाबाद में पेंटिंग का काम करता था। डेढ़ साल वहां रहने के बाद करीब दो महीने पहले ही गांव लौटा था। एक दिन मैं कृष्णा की बहन से मिलने गया था। घर के पीछे हम दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर बात कर रहे थे, तभी कृष्णा वहां पहुंच गया। उसने हम दोनों को देख लिया। बाद में उसने यह बात अपने पिता से बता दी। उसके पिता ने मुझे समझाया और कहा कि 'बउआ सुधर जाओ... वरना गलत होगा।' तब मैंने कहा था कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा।" यह कबूलनामा है, घाटमपुर के कठेठा गांव में 15 वर्षीय प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह की हत्या करने वाले आरोपी आशुतोष सिंह का। मंगलवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने

बताया कि कृष्णा की बहन से उसका प्रेम प्रसंग था और इसी बात के खुल जाने के डर ने कृष्णा को मार डाला। उसने बताया कि कृष्णा शारीरिक रूप से उससे कमजोर था। उसने अचानक उसे उठाकर खेत में पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़कर हाथों से गला दबाने लगा। जब वह छटपटाने लगा तो उसकी लोअर का नाड़ा निकालकर उसी से गला कस दिया और उसकी हत्या कर दी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया- कृष्णा के पिता ने गांव के ही बउरा और प्रभाकर पर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान परिजनों और संदिग्धों की कॉल डिटेल और सीडीआर खंगाली।

दूसरी बार देखे जाने के बाद दिमाग में बैठ गया डर

आरोपी ने बताया कि कृष्णा के पिता के समझाने के करीब पांच-छह दिन बाद वह फिर से कृष्णा की बहन से मिलने पहुंच गया था। इसी दौरान कृष्णा ने उसे दोबारा देख लिया। हालांकि, इस बार उसने यह बात अपने पिता से नहीं बताई, लेकिन यह बात आरोपी के दिमाग में घर बैठ गई कि कभी भी राज खुल सकता है। आरोपी आशुतोष ने बताया कि 7 मार्च की सुबह उसकी कृष्णा से कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। उसी दिन कृष्णा ने अपने पिता से कहा कि खेत में गाय घुस गई है, उसे निकालने जा रहे हैं। इसके बाद वह उसके पास आया और बोला, "मामा खेत चलोगे?" इस पर वह उसके साथ खेत की ओर चल पड़ा।

जांच में सामने आया कि आशुतोष की मृतक के घर के नंबर पर काफी बातचीत होती थी। पुलिस ने सोमवार को आशुतोष को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी ने बताया- खेत तक जाते समय उसके मन में हत्या जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन, लौटते समय अचानक उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर कृष्णा ने यह बात घर में बता दी तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

परिजनों के साथ कृष्णा को खोजने का नाटक करता रहा

हत्या करने के बाद आशुतोष अपने घर चला गया। वहां से वह गजनेर में ठेकेदार के पास चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। शाम करीब चार बजे जब वह गांव लौटा तो पता चला कि कृष्णा के परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। कृष्णा के चाचा ने आशुतोष को फोन कर कहा कि "बउआ मिल नहीं रहा है, घर आओ।" इसके बाद वह कृष्णा के घर पहुंचा और बाइक से परिजनों के साथ ढूंढने का नाटक करने लगा। इसी बीच देखा तो कृष्णा के पिता उसकी लाश सड़क किनारे रखकर रो रहे थे।

खेत के पास मिला था कृष्णा का शव

दरअसल, घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव निवासी संतोष सिंह के 15 वर्षीय बेटे प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह का शव शनिवार को खेत के पास माइनर किनारे पड़ा मिला था। उसकी लोअर के नाड़े से गला घोंटकर हत्या की गई थी। घटनास्थल के पास किशोर की साइकिल स्टैंड में ताला लगी खड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद रविवार शाम परिजनों ने मूसानगर घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।

डीसीपी साउथ ऑफिस में आरोपी आशुतोष ने सिलसिलेवार हत्या की पूरी कहानी बताई।

मौलाना का पुतला फूंक रहे करणी सेना के पदाधिकारी झुलसे

लखनऊ। लखनऊ में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का पुतला फूंकते समय बड़ा हादसा हो गया। आग से करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश और प्रदेश उपाध्यक्ष झुलस गए। दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। उन्हें बचाने के चक्कर में कई कार्यकर्ता भी मामूली रूप से झुलस गए। पुलिसकर्मियों ने अग्निशमन संयंत्र से आग पर काबू पाया। मौलाना अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया है। इसके बाद से प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज शाम हजरतगंज में मौलाना अब्दुल्ला का पुतला फूंकने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुतले को जूते से पीटा। उसके बाद पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की ऊंचीं लपटें निकलीं। प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हाथ और पैर झुलस गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। रमेश सिंह ने कहा कि कल से करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बिहार जाना शुरू होगा।

पृष्ठ 01 का शेष...

यूपी के 12,200...

इस सेवा का लाभ विद्यार्थियों के अलावा कचहरी, ऑफिस या अपना उत्पाद शहर में बेचने जाने वाले लोगों को भी मिलेगा। कई गांवों में ऐसी सड़कें हैं, जहां बड़ी बसें टर्न होने में परेशानी होती है। 12,200 में से 5000 ऐसे गांव हैं, जहां बड़ी बसें टर्न नहीं हो सकतीं। इसलिए ये छोटी बसें होंगी, जिनकी अधिकतम लंबाई सात मीटर और अधिकतम सीट क्षमता 28 होगी।

ईरान पर आज...

यह बयान ऐसे समय आया है जब टीम के पांच खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीम के खिलाड़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईरान के जनरल प्रॉसीक्यूटर के कार्यालय ने भी बाकी खिलाड़ियों को "शांति और भरोसे" के साथ देश लौटने का निमंत्रण दिया है। दरअसल 3 मार्च को एशियन कप टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले ईरान के राष्ट्रगान के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने मौन रहकर विरोध जताया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के पांच खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग ली है। ईरान ने मंगलवार को UAE की राजधानी अबू धामी में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जिससे वहां पर आग लग गई। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला रुवैस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हुआ, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रुवैस, अबू धाबी शहर से करीब 240 किलोमीटर पश्चिम में अल धाफरा क्षेत्र में स्थित है। यह जगह पहले एक छोटा सा तटीय इलाका थी, लेकिन अब यह UAE के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और औद्योगिक केंद्रों में से एक बन चुकी है। रुवैस कॉम्प्लेक्स की रिफाइनिंग क्षमता करीब 9.22 लाख बैरल कच्चे तेल और कंडेनसेट प्रतिदिन है। इसी वजह से यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरियों में भी शामिल है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा- "हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यह सब हमारे तय समय और हमारी शर्तों पर होगा।" हेगसेथ ने कहा, "आज ईरान के अंदर हमलों का अब तक का सबसे बड़े दिन होगा। सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, सबसे ज्यादा बमवर्षक और सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे। हमारी खुफिया जानकारी पहले से कहीं ज्यादा सटीक और मजबूत है।" हेगसेथ ने यह भी कहा कि ईरान लगातार कमजोर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी हैं, वह अब तक की उसकी क्षमता के मुकाबले सबसे कम रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा है कि कोई भी ताकत ईरान को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ईरान कम से कम 6,000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान कायम रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में पजशकियान ने कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने का सपना देखते हैं, वे इतिहास को नहीं समझते। उनके मुताबिक कई आक्रांताओं ने ईरान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। उन्होंने कहा कि हमलावर आते-जाते रहे, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा है और आगे भी रहेगा। नीदरलैंड ने ईरान में बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच तेहरान स्थित अपने दूतावास से स्टाफ हटाने का फैसला किया है। डच सरकार ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए दूतावास की गतिविधियां अस्थायी रूप से अजरबैजान की राजधानी बाकू से संचालित की जाएंगी। सरकार के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ते जोखिम को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हालात सामान्य होने के बाद व्यवस्था की फिर से समीक्षा की जाएगी। डच अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण दूतावास की गतिविधियों को फिलहाल ईरान से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप खेलने गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम को सरकार ने देश लौटने का भरोसा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि खिलाड़ियों को "खुले दिल से" स्वागत के साथ वापस बुलाया जा रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब टीम के पांच खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीम के खिलाड़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईरान के जनरल प्रॉसीक्यूटर के कार्यालय ने भी बाकी खिलाड़ियों को "शांति और भरोसे" के साथ देश लौटने का निमंत्रण दिया है। दरअसल 3 मार्च को एशियन कप टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले ईरान के राष्ट्रगान के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने मौन रहकर विरोध जताया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के पांच खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग ली है। रुवैस कॉम्प्लेक्स की रिफाइनिंग क्षमता करीब 9.22 लाख बैरल कच्चे तेल और कंडेनसेट प्रतिदिन है।

40 लाख...

सरमा ने कहा कि हर महीने 10 तारीख को, लगभग 40 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को अपने बेसिक खर्चों के लिए 1,250 रुपये मिलते हैं।

आलू के गिरते दाम पर अखिलेश का हमला

बोले- किसानों के प्रति लापरवाह है भाजपा सरकार

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आलू के दाम गिरने से किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन किसान और खेती विरोधी भाजपा सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलू किसानों की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को केवल अपनी राजनीतिक सत्ता से मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं और परेशानियों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीति ऐसी है कि फसलों के दाम इतने कम हो जाएं कि किसानों की लागत भी न निकल सके।

इससे किसान हताश होकर खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएं और अपनी जमीनें कौड़ियों के दाम पर बेच दें। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे बड़े पूंजीपति किसानों की जमीन खरीद लेंगे और वही किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की मंशा किसानों की जमीन पर कब्जा कर बड़े स्तर पर खेती करने और खाद्यान्न उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेने की है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com
स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।
सम्पादक : विद्यादेवी
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा
समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676